श्री मंगुभाई पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधान सभा अधिवेशन

12, माघ–फाल्गुन, 1945 शक भोपाल, बुधवार, 07 फरवरी, 2024

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत।
2. सोलहवीं विधानसभा के वर्तमान सत्र में सदन को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आजादी के अमृतकाल में भारतीय स्वातंत्र्य एवं भारतीय गणतंत्र दोनों के अमृत महोत्सव का साक्षी बनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं देश की स्वाधीनता और सम्प्रभुता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले क्रांतिकारियों, महापुरुषों और जननायकों को शत-शत प्रणाम करता हूँ। मध्यप्रदेश विधानसभा की समृद्ध परंपराओं और सशक्त कार्यप्रणाली ने संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया है। यदि भारत लोकतंत्र की माता है तो यह सदन लोकतंत्र का मंदिर।
3. अयोध्या में भगवान श्रीराम की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के भव्य समारोह ने भारत ही नहीं, पूरे

विश्व को श्रद्धा, भक्ति और आस्था से सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रामराज्य की परिकल्पना और विकसित भारत की संकल्पना, दोनों को साकार होते देखना निश्चय ही एक अद्‌भुत-अभूतपूर्व-अविस्मरणीय अनुभव है। चित्रकूट एवं ओरछा सहित प्रदेश की सीमाओं में सम्पूर्ण राम वन गमन पथ के सर्वांगीण विकास के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश भर में जहाँ-जहाँ भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत की भूमि पर शूरवीरों की एक महान परम्परा रही है। मेरी सरकार ने शूरवीरों के जीवन एवं बलिदान के प्रति आदरांजलि एवं भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्वरूप वीर भारत संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया है।

4. भारत की अर्थव्यवस्था पर हाल ही में जारी रिपोर्ट विगत लगभग 10 वर्ष में आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान की नई ऊँचाइयों को छूने में मिली अपार सफलता की कहानी बयाँ करती है। जहाँ दुनिया की बड़ी अर्थ व्यवस्थाएँ 3% से अधिक की विकास दर पाने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं, वहीं भारत की विकास दर लगातार 3 वर्षों से 7% से अधिक बनी हुई है। आज देश की 78% से अधिक महिलाओं के पास अपना बैंक अकाउंट है। देश के श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 37% हो गई है। बेटियों का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 4 गुना से भी अधिक और हायर सेकेण्डरी शिक्षा में 2 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। जन-कल्याण की अवधारणा अब जन-सशक्तिकरण का रूप ले चुकी है।

5. वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट अमृत-काल का बजट है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये अंतरिम बजट दूरदर्शी, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास और कल्याण पर इसमें फोकस किया गया है। ये सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को सार्थक करने वाला है। विकास के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल-तीनों प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने का संकल्प बजट में किया गया है। यह गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं, सभी को सशक्त बनाने वाला बजट है।

6. ये नए भारत का समय है, ये विश्व-मित्र भारत का समय है, ये अमृत-पीढ़ी की ऊर्जा से प्रगति के नए प्रतिमान रचने का समय है, ये प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का समय है, ये इक्कीसवीं सदी के हर क्षेत्र में अग्रणी मध्यप्रदेश को गढ़ने का समय है। मेरी सरकार एक ऐसी डबल इंजन सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के चौतरफा विकास और जन-जन के कल्याण के लिए नीतियाँ बना रही है, निर्णय ले रही है और सुराज के सपने सच करके दिखा रही है।

7. मध्यप्रदेश में विकसित भारत संकल्प-यात्रा, माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष-2047 तक विकसित भारत के निर्माण की प्रबल अभिव्यक्ति बनकर उभरी है। यात्रा के दौरान केन्द्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। मेरी सरकार ने संकल्प-पत्र-2023 में प्रदेश की जनता के कल्याण के संकल्पों पर तेज गति से कार्य प्रारंभ

कर दिया है, जिसके चलते विकास की परिकल्पनाएँ सुखद परिणामों में परिवर्तित होने लगी हैं।

8. मेरी सरकार के प्रयासों से अधोसंरचनात्मक पूँजीगत कार्यों पर अधिक से अधिक व्यय कर अर्थव्यवस्था को तेज गति से विकसित किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 56 हजार 256 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पूँजीगत व्यय का लक्ष्य है।

9. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और निर्णय-कौशल की बदौलत केन-बेतवा परियोजना की भाँति पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना की स्वीकृति प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 35 हजार करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों-शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर और देवास को

पेयजल एवं 3 लाख 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। संकल्प-पत्र 2023 के संकल्प को पूरा करने के लिए नर्मदा कछार की 1 लाख 12 हजार हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता की 3 परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

10. भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की 724 किलोमीटर लंबी 24 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। इन परियोजनाओं से न केवल उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थलों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी एवं सीमावर्ती राज्यों के बीच यातायात सुगम हो सकेगा। मेरी सरकार के प्रयासों से इस वर्ष अब तक 3 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का

सुदृढ़ीकरण एवं 4 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का नवीनीकरण हो चुका है।

11. मेरी सरकार घरेलू, औद्योगिक एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय सुनिश्चित कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में विद्युत क्षमता में 5 हजार मेगावॉट से अधिक की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य है। मेरी सरकार के प्रयासों से नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में विगत 11 वर्षों में लगभग 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति और सौर ऊर्जा क्षमता में मध्यप्रदेश, देश के टॉप-टेन राज्यों में शामिल है। ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के साथ-साथ बिरसिंहपुर, इंदिरा सागर एवं गांधी सागर जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकास हेतु तकनीकी सर्वे कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत प्रदेश में 75 हजार सोलर रूफटॉप स्थापना का लक्ष्य है।

12. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष मिलाकर 17 जिलों को आधारभूत संरचना विकास हेतु 126 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है।

13. मेरी सरकार गरीबों के कल्याण और उत्थान की चिंता करने वाली सरकार है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में मध्यप्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। बड़ी आबादी को बहुआयामी गरीबी से उबारने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश, देश में तीसरे स्थान पर है।

14. इंदौर स्थित हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को उनके हक की राशि 224 करोड़ रुपए के भुगतान की पहल कर लंबे

समय से संघर्ष कर रहे मजदूरों को यदि किसी ने न्याय दिलाया है तो वह माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरी सरकार ने दिलाया है। प्रदेश की अन्य मिलों में भी ऐसे प्रकरणों में मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित करने के लिए सरकार हर संभव उपाय करेगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए कर मेरी सरकार ने संकल्प-पत्र में दी गई गारंटी को पूरा किया है।

15. संबल योजना के अंतर्गत 5 लाख 25 हजार से अधिक हितग्राहियों को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए की राशि हितलाभ के रूप में वितरित की गई है। जल जीवन मिशन अंतर्गत अब तक प्रदेश के 12 हजार से अधिक ग्रामों के शत-प्रतिशत घरों में नल से जल पहुँचाया जा चुका है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हर पात्र गरीब परिवार के अपने घर का सपना सच हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में 140% उपलब्धि अर्जित कर मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। दिव्यांगजन कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले वित्तीय वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से लगभग 60 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

16. मेरी सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सदैव ही संवेदनशील रही है। प्रदेश के 2 हजार 600 से अधिक छात्रावासों एवं आश्रमों में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के छात्र-छात्राओं को इस वर्ष अब तक नि:शुल्क सुविधाओं तथा शिष्यवृत्ति के रूप में 325 करोड़ रुपए से अधिक और छात्रवृत्ति के रूप में 102 करोड़